www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 204 | जौनपुर गुरूवार, 12 मार्च 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

भाजपा का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगी है कांग्रेस : संजय सरावगी

पटना, (एजेंसी)। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार में जिस तरह चुनाव प्रचार कर रहे थे और बार–बार उन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे लेकिन आम जनता ने इसे नकार दिया और कांग्रेस का सफाया कर दिया। उनके पास विधायकों की संख्या नाममात्र की है। संजय सरावगी ने कहा कि पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में भी एसआईआर हुआ और एक भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं गया। इन बातों का जनता पर असर नहीं होता। मुद्दों को भटकाने वाली बातों को आम जनता नकार चुकी है। कांग्रेस का तो चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। कांग्रेस भाजपा का विरोध करते–करते देश का विरोध करने लगी है। देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।बता दें कि देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर के बाद मतदाताओं के नाम कटने का आरोप लगा रही हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 10 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में एसआईआर को धोखाधड़ी करार दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर को लेकर राज्यसभा में कहा था कि एसआईआर के नाम पर हर जगह धोखाधड़ी हो रही है। यह सबसे बुरा है और सारी कवायद चुनाव जीतने के लिए हो रही है। इस तरह की कवायद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में हो रही है। हर जगह और हर राज्य में धोखाधड़ी ही धोखाधड़ी है।बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 9 मार्च को आरोप लगाया था कि राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के जरिए ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूछा राज्यपाल बागडे का हाल

जयपुर, (एजेंसी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे की कुशलक्षेम पूछी। श्री शर्मा ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर श्री बागडे से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान श्री शर्मा ने चिकित्सकों से राज्यपाल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।श्री देवनानी भी अस्पताल पहुंचे और श्री बागडे से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री देवनानी ने राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंगलवार रात को ही हुए श्री देवनानी के पुस्तक विमोचन समारोह में राज्यपाल के आने का कार्यक्रम था लेकिन दोपहर को अचानक उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले तमिलनाडु को 5650 करोड़ की सौगात देंगे

चेन्नई, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम 6.30 बजे वह एनडीए रैली को संबोधित भी करेंगे, जहां एआईएडीएमके, पीएमके, एएमएमके और टीएमसी के नेता भी मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का शिलान्यास करेंगे, जो निलगिरी और एरोड जिलों में 3,680 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ कार्यान्वित होगा। इससे 8.8 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन, 200 से अधिक व्यावसायिक संस्थानों को

गैस और 201 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन उपलब्ध होंगे। साथ ही, पीएम मोदी ल्यूब प्लांट, मणाली, चेन्नई का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट की क्षमता 672 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो भारत की ल्यूब्रिकेंट्स निर्माण क्षमता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 370 किमी लंबी 89 ग्रामीण सड़कें का उद्घाटन करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही वह एफ–81 पर गंगाइकोंडा चोलापुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास का शिलान्यास करेंगे। मोदी दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, दो एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इससे तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए डीएमके सरकार को राज्य में बेहतर प्रशासन स्थापित करेगी। जनता अच्छे प्रशासन और विकास के लिए एनडीए को समर्थन देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डीएमके अब एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता से चिंतित है। योजनाओं से थक चुके हैं और विकास की दिशा में एनडीए के एजेंडे से जुड़ रहे हैं।

तरनजीत सिंह संधू बनेंगे दिल्ली के 23वें लेफ्टिनेंट गवर्नर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1:30 बजे लोक निवास में होगा, जहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाएंगे, और औपचारिक रूप से उन्हें राष्ट्रीय राजधानी का 23वां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करेंगे। अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है और वे शुक्रवार को पदभार संभालेंगे। तरनजीत सिंह संधू एक पूर्व भारतीय डिप्लोमैट हैं, जिन्होंने फरवरी 2020 से 31 जनवरी, 2024 तक ˆ में भारत के राजदूत के रूप में काम किया। संधू, जो 1988 में इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए थे, को यूक्रेन में भारतीय दूतावास खोलने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने यूक्रेन में भारतीय दूतावास में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन विंग के हेड के रूप में काम किया। वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी से लेकर फ्रैंकफर्ट में इंडिया के कॉन्सुल जनरल और वॉशिंगटन डी.सी. में इंडियन एम्बेसी में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन तक, संधू ने अपने

साढ़े तीन दशक से ज्यादा के करियर में कई अहम डिप्लोमैटिक काम किए। रिटायर होने के बाद, संधू 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ठश्रच ने संधू को अमृतसर से कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औजला के खिलाफ अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया। तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स पूरा किया।

भरे भंडार को देख दुनिया कर रही है वाह–वाह – शिवराज सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 357 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय दोनों मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने करीब 150 मिलियन टन से अधिक चावल उत्पादन के साथ चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है, जबकि गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों में भी रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ है। केंद्रीय

मंत्री के अनुसार, पहले भारत को पीएल–480 के तहत आयातित गेहूं पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज हालात यह हैं कि देश के गोदाम गेहूँ और चावल से भरे पड़े हैं और सरकार को चिंता इस बात की है कि "रखे कहाँ", जबकि दुनिया भारत के किसानों और नीतियों की सराहना कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फलों और सब्जियों के साथ–साथ दालों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी करवाई है जिससे कुल उर्वरक उपयोग और लागत में कमी के साथ पौष्टिक आहार की उपलब्धता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि दालों का उत्पादन लगभग 19 मिलियन टन से बढ़कर 25दृ26 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया है।

सीएम योगी का निर्देश, जून तक पूरा कर लें बीडा के लिए भूमि अधिग्रहण

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रस्तावित विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को प्रगति समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ–पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि इन परियोजनाओं के लिए भूमि क्रय की प्रक्रिया को अविलंब गति देते हुए सभी बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि

एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार प्रदेश में निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संतुलित विकास को नई गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए मजबूत अवसंरचना आधार अत्यंत आवश्यक है और किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा, उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। समीक्षा में बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य कैरिजवे निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से पूर्ण किए जा रहे हैं।सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सभी शेष कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे कर एक्सप्रेसवे को शीघ्र संचालन के लिए तैयार किया जाए।

जनता कब तक सहेगी प्रियंका गांधी ने एल पी जी संकट पर संसद में चर्चा की मांग की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को संसद में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति में जारी व्यवधान पर चर्चा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और सिलेंडरों की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का बोझ लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती। संसद में बहस से महत्वपूर्ण जनहितैषी मुद्दों को उठाने का अवसर मिलेगा, यह कहते हुए कांग्रेस नेता ने संकट को और भी बदतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि जनता कब तक सहन करेगी? कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, एलपीजी की स्थिति देखिए, यह सब उनकी नीतियों और योजनाओं के कारण है। अगर संसद में चर्चा हो पाती तो अच्छा होता, कम से कम जनहितैषी मुद्दों

को तो उठाया जा सकता था। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच, केंद्र ने हाल ही में खाना पकाने के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस बढ़ोतरी के बाद, दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमत 913 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये, मुंबई में 912 रुपये और चेन्नई में 928 रुपये हो गई है। विभिन्न राज्यों में कीमतों में अंतर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लागू करों के कारण होता है। कई सांसदों ने एलपीजी सिलेंडरों की हालिया मूल्य वृद्धि पर चर्चा की मांग की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआइ) के सांसद पी. संदोष कुमार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश भर में सिलेंडरों की कथित कमी पर चर्चा के लिए आज राज्यसभा में कार्यविराम प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सांसदों ने एलपीजी सिलेंडरों के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि और मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कमी ने नागरिकों के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा कर दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच एलपीजी की कमी उत्पन्न हुई है।

तेजस्वी यादव का दावा– हमारे पास संख्या है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं

पटना, (एजेंसी)। बिहार में राज्यसभा चुनाव में छह प्रत्याशियों के मैदान में उतर जाने के बाद मतदान होना तय है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। इस बीच, राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई। कहा जा रहा है कि इस बैठक के जरिये चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की गई। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक बेहद सकारात्मक रही और सभी सहयोगी दलों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में हम लोग निश्चिंत हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा।आवश्यक संख्या बल को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "हमारे पास संख्या है, तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं।" इधर, बैठक के बाद पूर्व मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर ने कहा कि

साम्प्रदायिक पार्टियां और विचार देश के लिए खतरा हैं। उनके खिलाफ सोशल जस्टिस की पार्टियां एक हैं। उन्होंने कहा कि यह मात्र गेट–टू–गेदर था। सभी निश्चिंत हैं कि हमारी जीत तय है। दरअसल, बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें इस बार खाली हो रही हैं और इन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में पांच जबकि राजद ने एक प्रत्याशी उतारे हैं। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए।

तिलकधारी महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र 2025– 26 के अंतर्गत तृतीय एक दिवसीय सामान्य शिविर का आयोजन सम्पन्न

देश की उपासना ब्यूरो

जौनपुर। तिलकधारी महिला महाविद्यालय जौनपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र 2025– 26 के अंतर्गत तृतीय एक दिवसीय सामान्य शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ0 वंदना सिंह द्वारा किया गया तत्पश्चात जागरूकता अभियान के अंतर्गत शिक्षा जागरूकता, साफ– सफाई जागरूकता,मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति स्वयं सेविकाओं को तैयार किया गया। जिसे वे गांव में घर–घर जाकर जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार कर सके। कार्यक्रम अधिकारी डॉ0 नीलम सिंह और डॉ0 चित्रलेखा सिंह द्वारा स्वयं सेविकाओं को निस्वार्थ भाव से कार्य कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। श्री अनूप कुमार सिंह ने स्वयं सेविकाओं को शुभकामनाएं दी। तथा इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की अन्य सभी प्राध्यापिकाएं ने अपनी सहभागिता देकर कार्यक्रम को सफल बनाया

राष्ट्रपति आगमन को लेकर सीएम योगी ने ट्रस्ट व पदाधिकारियों के संग मंदिर परिसर का निरीक्षण कर किया समीक्षा बैठक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। गुरूवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचकर राम नवमी व 19 मार्च को राम नगरी आ रही राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी आदित्य नाथ राम नगरी आकर ट्रस्ट के पदाधिकारियों व अधिकारियो संग समीक्षा बैठक किया।इस मौके पर उन्होंने अधिकारियो को आवश्यक दिशा निर्देश दियें।समीक्षा बैठक से पहले उन्होंने संकटमोचन हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन–पूजन किया और प्रदेश की सुख–शांति की कामना की। इसके बाद सीएम योगी ने श्री राम मंदिर में श्रीरामलला के चरणों में शीश झुकाया।उन्होंने श्रीराम मंदिर परिसर मे निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत संकटमोचन हनुमानगढ़ी मंदिर से की।उन्होंने यहां विधिवत पूजा–अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की।यहां से निकल कर मुख्यमंत्री श्रीराम मंदिर पहुंचे।यहां उन्होंने श्रीरामलला के दर्शन किए, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में संतों से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना।मुख्यमंत्री यहां सबसे पहले महंत प्रेमदास जी महाराज से मिले।इसके बाद मुख्यमंत्री ने अन्य संतों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। इससे पहले मुख्यमंत्री के अयोध्या

आगमन पर रामकथा पार्क हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर जनपद के प्रभारी मंत्री/कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, अमित सिंह चौहान, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय आदि मौजूद रहे।समीक्षा बैठक मे इनके अलावा एडीजी प्रवीण कुमार,कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी डाक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

संपादकीय

मुकदमे की कार्यवाही

हालिया न्यायिक निर्णयों ने इस धारणा की पुष्टि की है कि सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल हुआ। जिन साक्ष्यों के आधार पर अभियोग दर्ज हुए, उनका सख्त न्यायिक परीक्षण हुआ, तो अधिकांश मामलों में वे टिक नहीं पाए। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामला खारिज करते हुए जज ने जो टिप्पणियां कीं, उन पर गौर करने के बाद शायद ही किसी के मन शक बचे कि ये पूरा मामला बदनीयती से गढ़ा गया था। उसके एक दिन पहले पंचकूला से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में भी ऐसा ही बड़ा फैसला आया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को क्लीन चिट दे दी। मामला पंचकूला में संस्थागत प्लॉट के दोबारा आवंटन से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2006 में इस निर्णय को विधिवत मंजूरी दी थी, इसलिए मामले में अनियमितता के सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। उसके पहले बीते दिसंबर में नेशनल हेराल्ड मामले में ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इन घटनाओं ने इस आम धारणा की पुष्टि की है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में सरकारी एजेंसियों का राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल हुआ है। एजेंसियों ने जिन कथित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग दर्ज किए, उनका जब सख्त न्यायिक परीक्षण हुआ, तो अधिकांश मामलों में वे टिक नहीं पाए। इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि ऐसे सारे मामलों में मुकदमे की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर चलाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किसी भी व्यक्ति पर सालों साल मुकदमों का साया डाले रखना या अभियुक्तों को जेल में रखना (जैसाकि दिल्ली दंगों और भीमा कोरेगांव जैसे मामलों हुआ है) किसी रूप में उचित नहीं है। इससे भारत में प्रक्रिया ही दंड है– जैसी दुर्भाग्यपूर्ण धारणा लोगों के मन में गहराती चली गई है। सर्वोच्च न्यायपालिका ने जमानत जैसे बुनियादी तकाजे के बारे में भी तत्परता ना दिखाकर ऐसी धारणा को मजबूत किया है। नतीजतन, आपराधिक न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। अतरू सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित होगा कि वह राजनीतिक प्रकृति के तमाम संदिग्धा मामलों में जल्द सुनवाई सुनिश्चित कराए।

साधु संत भी राजनीतिक लाइन पर बंटे

अजीत द्विवेदी

उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानमंद के साथ जो हो रहा है वह भारतीय समाज के अंदर पल रही एक बड़ी बीमारी का लक्षण है। वह बीमारी धार्मिक और सामाजिक विभाजन की है, जिसे राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ाया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि देश और समाज इस कदर निभाजित हुआ है। पहले समाज के स्तर पर विभाजन चुनावों के समय दिखते थे। हालांकि वह भी बहुत सीमित होता था। लेकिन आज स्थायी रूप से एक विभाजन दिखता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि नेताओं के साथ साथ धर्मगुरु, आध्यामिक कार्यों में लगे लोग और साधारण से लेकर शंकराचार्य के स्तर तक साधु संत भी राजनीतिक लाइन पर बंटे हुए हैं।

लोग साधु, योगी और कथावाचक की जाति खोज ले रहे हैं और फिर उस आधार पर उसके समर्थन या विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह किसी स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है। केंद्र की मौजूदा सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए सुनियोजित तरीके से इस विभाजन को बढ़ा रही है। शंकराचार्य का मामला और यूजीसी की नियमावली इसके दो ताजा संकेत हैं। बहरहाल, यह दुर्भाग्य है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत और इसके 140 करोड़ लोगों के नैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने वाले साधु या संत या धर्मगुरू खोजने से नहीं मिलेंगे लेकिन नफरत फैलाते साधु संत चारों तरफ मिल जाएंगे। इतिहास में कभी भी भारत की आध्यात्मिक परंपरा ऐसी नहीं रही थी। ईसाई धर्मगुरू भड़काऊ बातें करते थे और झूठे सच्चे वादे करके धर्म परिवर्तन कराते थे या इस्लाम के प्रचारक मौलाना आदि भड़काऊ भाषणों से लोगों को उकसाते थे, जिहाद के लिए प्रेरित करते थे लेकिन हिंदू साधु संत इस तरह के काम नहीं करते थे। यह अंतर बहुत साफ दिखता था और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बुनियादी रूप से ईसाई और इस्लाम दोनों राजनीतिक धर्म हैं, जो लालच या भय से फैलाए गए हैं। महात्मा गांधी ने साम्राज्यवाद को फैलाने वाली शक्तियों के तौर पर ईसाई पादरियों और चर्च को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि पहले इनके पादरी आते हैं, फिर इनके व्यापारी आते हैं और अंत में इनकी सेना आती है। इसी तरह इस्लाम तलवार के दम पर फैलता है यह आरोप अक्सर लगते रहते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हिंदू धर्म को लेकर नहीं कही जाती हैं तो इसका कारण यह था कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य हों या दूसरे साधु संत हों वे समाज सुधार के कार्यों में रहते थे या धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के उपक्रमों में रहते थे। समय के साथ साथ इसमें बड़ा बदलाव आया है। अब भारत के साधु संत खुल कर राजनीति की बातें करते हैं। पार्टियों और नेताओं का समर्थन करते हैं। पांच हजार साल की सनातन परंपरा से अलग हट कर इस या उस नेता को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में रेखांकित करते हैं। सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली बातें करते हैं। जाति और धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणियां करते हें, जैसी टिप्पणी करने से नेता भी हिचकते हैं। देश के सम्मानित माने जाने वाले साधु संत महिलाओं को लेकर ऐसी अनर्गल बातें करते हैं, जिन्हें सुन कर सिर शर्म से झुक जाता है। आज साधु संतों का आकलन उनकी योग्यता या धार्मिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों के आधार नहीं किया जाता है, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि उसके आश्रम में कितनी भीड़ जुटती है, उसके आगे पीछे कितनी गाड़ियां चलती हैं, उसके आश्रम में कौन नेता, अभिनेता या खिलाड़ी पहुंचा, उसे कैसी सुरक्षा मिली हुई है आदि आदि। अगर धर्मगुरू चार्टर्ड फ्लाइट से चलता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाएगा भले उसकी बातें कितनी भी मूर्खतापूर्ण और समाज का विभाजन करने वाली क्यों न हों। यह स्थिति एक राष्ट्र और समाज के रूप में भारत को रसातल में ले जा रही है। बहरहाल, विषयांतर हो गया लेकिन प्रयागराज वे माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ जो हुआ और अब जिस तरह से एक दूसरे संत के हिस्ट्रीशीटर शिष्य द्वारा उनके खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज कराया गया है वह इस गंभीर व्याधि का एक लक्षण है। सबको पता है कि अविमुक्तेश्वरानंद वाचाल हैं। वे शंकराचार्य स्वरूपानंद के शिष्य हैं और अपने गुरू की तर्ज पर खूब बयानबाजी भी करते हैं। उनके बयान अक्सर भाजपा और उसकी केंद्र व राज्यों की सरकारों के खिलाफ होते हैं। उन्होंने पिछले साल के कुंभ मेले में हुई भगदड़ और उसकी मौतों को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। इस आधार पर उनको भाजपा विरोधी और कांग्रेस समर्थक साधु माना जाता है। हालांकि वे कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी बोलते रहते हैं। प्रयागराज में उनके साथ जो हुआ और उसके बाद से जो हो रहा है वह उनकी राजनीतिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है। शुरुआत मौनी अमावस्या के दिन हुई, जब वे अपनी पालकी से शाही स्नान के लिए जा रहे थे और उनकी पालकी रोक दी गई है। प्रोटोकॉल का हवाला दिया गया। जब उनके शिष्यों ने आगे बढ़ने का उपक्रम किया तो बल प्रयोग करके सबको रोका गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पालकी की क्षत्रप टूट गई और उनके शिष्यों को, जिनमें वेदपाठी ब्राह्मण बटुक थे, गिरा गिरा पर लातों, घूसों से पीटा गया।

यूरोप का हुआ बुरा हाल, रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देश अब मास्को से मांग रहे गैस और तेल

नीरज

जो यूरोप कल तक रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा था और उससे गैस तथा तेल खरीदने वाले देशों पर पेनल्टी लगाने की मांग करते हुए यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा था, वही यूरोप अब मध्य पूर्व में संकट गहराते ही फिर से रूस की ओर देखने लगा है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष तथा फारस की खाड़ी में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में ऊर्जा संकट से जूझता यूरोप रूस से गैस और तेल की संभावित आपूर्ति को लेकर नई चर्चा कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों में रूस को अप्रत्याशित लाभ की स्थिति में ला खडा किया है। हम आपको बता दें कि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। फारस की खाड़ी के प्रमुख समुद्री मार्ग हार्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। ईरान से जुड़े तनाव और संभावित आपूर्ति बाधा की आशंका के कारण तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। सप्ताह की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत प्रति बैरल सौ डॉलर से ऊपर पहुंच गई। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद कीमतों में कुछ गिरावट आई, फिर भी युद्ध से पहले की

तुलना में तेल करीब सत्ताइस प्रतिशत महंगा बना हुआ है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ रूस को मिल सकता है। रूस पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने उस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के कारण इन प्रतिबंधों का प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है। ऊंची कीमतों के कारण रूस को अपने तेल निर्यात से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका ने भारत को भी कथित रूप से अस्थायी छूट देते हुए रूसी कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दी है। इस निर्णय के बाद रूस के तेल निर्यात में तेजी आई है। पहले जहां रूसी तेल लगभग पचास डॉलर प्रति बैरल के आसपास बिक रहा था, वहीं अब इसकी कीमत करीब नब्बे डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इससे रूस को राजस्व में भारी बढ़ोतरी मिल रही है। ऊर्जा बाजार के आंकड़े बताते हैं कि समुद्र में टैंकरों पर जमा रूसी तेल का भंडार भी तेजी से कम हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि खरीदार देशों तक आपूर्ति तेजी से पहुंच रही है। फरवरी के अंत तक जहां टैंकरों में लगभग एक सौ बत्तीस मिलियन बैरल रूसी तेल जमा था, वहीं अब यह घटकर करीब एक सौ अठारह मिलियन बैरल रह गया है। इसका अर्थ है कि वैश्विक बाजार में रूसी तेल की मांग फिर बढ़ने लगी है। यदि मध्य पूर्व में संघर्ष लंबा चलता है और खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात बाधित होता है तो रूस को अरबों डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊंची कीमतों और आपूर्ति संकट के चलते रूस को आय में कई अरब डॉलर का अतिरिक्त लाभ हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी संकेत दिया है कि यदि यूरोपीय देश राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर दीर्घकालिक सहयोग चाहते हैं तो रूस उन्हें फिर से तेल और गैस आपूर्ति करने को तैयार है। पुतिन का कहना है कि रूस ने कभी यूरोप के साथ ऊर्जा सहयोग से इंकार नहीं किया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने स्वयं रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने का निर्णय लिया था। हम आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप अपनी गैस जरूरतों का चालीस प्रतिशत से अधिक हिस्सा रूस से खरीदता था। लेकिन प्रतिबंधों और वैकल्पिक स्रोतों की खोज के कारण यह हिस्सा घटकर वर्ष 2025 तक लगभग तेरह प्रतिशत रह गया। यूरोपीय संघ ने समुद्री मार्ग से आने वाले रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था और कई पाइपलाइन मार्ग भी बंद हो गए थे। हालांकि मौजूदा संकट में स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। यूरोप ने अभी तक रूसी तरल प्राकृतिक गैस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू नहीं किया है और प्रस्तावित योजना के अनुसार इसे 2027 तक धीरे धीरे समाप्त किया जाना है। इस कारण यूरोप के कुछ देश आपूर्ति संकट की स्थिति में फिर से रूसी गैस खरीदने पर विचार कर सकते हैं। फिर भी रूस की क्षमता पूरी तरह असीमित नहीं है। वर्षों से लगे प्रतिबंधों और यूक्रेन से हुए हमलों के कारण उसकी ऊर्जा अवसंरचना के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जहाजरानी और बीमा से जुड़ी बाधाएं भी रूसी निर्यात को सीमित करती हैं। वैसे रूस का अधिाकांश तेल फिलहाल भारत और चीन जैसे सीमित खरीदारों को ही जा रहा है। इसके बावजूद मौजूदा वैश्विक परिस्थिति का सामरिक महत्व बहुत बड़ा है। मध्य पूर्व में युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बना हुआ है। रूस के पास विशाल तेल और गैस भंडार हैं और संकट के समय यह उसे आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह का प्रभाव प्रदान करते हैं। दूसरी ओर यूरोप के सामने भी एक कठिन विकल्प खड़ा हो गया है। यदि मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है तो उसे अपने पुराने ऊर्जा स्रोत यानी रूस की ओर फिर से देखना पड़ सकता है। इस प्रकार मध्य पूर्व का युद्ध केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा संतुलन और भू राजनीतिक शक्ति समीकरण को भी नए सिरे से आकार दे रहा है।

यूक्रेन तो अमेरिका–इजरायल से भी बड़ा खिलाड़ी निकला

अभिनय

रान के 'शाहेद' ड्रोन आज उसके सबसे अहम हवाई हथियारों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी तकनीक की प्रेरणा कभी इजराइल में विकसित ड्रोन प्रणालियों से मिली थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमित संसाधनों ने ईरान को मजबूर किया कि वह इन्हीं ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने स्वदेशी सैन्य कार्यक्रम का केंद्र बना दे। एक ऐसा शब्द जो दुनिया की तस्वीर बदल देता है। सुपर पावर जब भी यह शब्द सुनते हैं, तो जहन में अमेरिका, रूस, चीन का नाम आता है। लेकिन अब ऐसी कहानी जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य विशेषज्ञों को भी चौंका रही है। वो देश जो महज कुछ साल पहले तक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। आज उसी देश को दुनिया का अगला मिलिट्री सुपर पावर कहा जा रहा है। वो देश यूक्रेन है। दरअसल, मध्य–पूर्व में दशकों बाद अमेरिकी सैन्य ताकत की सबसे बड़ी तैनाती के बीच अमेरिका–ईरान टकराव का एक दिलचस्प और थोड़ा विडंबनापूर्ण पहलू सामने आया है। इस संघर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने चुपचाप अपना लो–कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम (स्न्ै) मैदान में उतारा। एक ऐसा एक–तरफा हमला करने वाला ड्रोन, जिसकी अवधारणा उसी सस्ती ड्रोन तकनीक से मिलती–जुलती है, जिसे ईरान कई दशकों से विकसित करता रहा है। ईरान के 'शाहेद' ड्रोन आज उसके सबसे अहम हवाई हथियारों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी तकनीक की प्रेरणा कभी इजराइल में विकसित ड्रोन प्रणालियों से मिली थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमित संसाधनों ने ईरान को मजबूर किया कि वह इन्हीं ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने स्वदेशी सैन्य कार्यक्रम का केंद्र बना दे। इनका मकसद पश्चिमी रक्षा प्रणालियों को सीधे चुनौती देकर हराना नहीं, बल्कि लगातार हमलों के जरिए उन्हें थका देना और उनके संसाधन खत्म करना है। इसी श्रृंखला का शुरुआती मॉडल शाहेद–131 था, जिसने सितंबर 2019 में सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और तभी से दुनिया को यह अहसास होने लगा कि सस्ते लेकिन घातक ड्रोन युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। जो शुरुआत में केवल एक सैन्य मजबूरी का उपाय था, वही समय के साथ एक वैश्विक हथियार बन गया। सबसे पहले ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन में हौती विद्रोहियों ने इन ड्रोन का इस्तेमाल किया और बाद में रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ईरान को पुतिन का सहयोगी तक कहा, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ रूस को शाहेद ड्रोन दिए बल्कि उन्हें बनाने की तकनीक भी उपलब्ध कराई। ब्रिटानिका के अनुसार सुपर पावर वो राष्ट्र है जिसे दुनिया की मंच पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिसके सहयोग के बिना दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या हल नहीं हो सकती। इतिहास में देखें तो अब तक केवल दो देशों को निर्विवाद सुपर पावर का दर्जा मिला है। अमेरिका और सोवियत संघ। आज भले ही रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को कुछ मापदंडों पर सुपर पावर कहा जाए लेकिन अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर है। लेकिन रूस से बीते् चार बरस से जंग ले रहा छोटा सा मुल्क यूक्रेन अभ चर्चाओं में है। यूक्रेन का कान्फिंडेंस कहे या सुपरपावर बनने की दिशा में कदम की अब उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की रक्षा के लिए ड्रोन विशेषज्ञों और इंटरसेप्टर ड्रोन की एक विशेष टीम भेजी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका ने हाल ही में सुरक्षा सहायता के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही अमेरिका की ओर से मदद मांगी गई, यूक्रेन ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपने विशेषज्ञों को भेजने का फैसला किया। राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि वे ईरानी ड्रोन को मार गिराने की विशेषज्ञता साझा करेंगे। यूक्रेन को रूस द्वारा दागे जाने वाले ईरानी डिजाइन के शाहेद हमलावर ड्रोनों के रात्रिकालीन हमलों का सामना करना पड़ता है। रूस तेहरान का सहयोगी है। यूक्रेन का कहना है कि इन हमलों को नाकाम करने में यूक्रेन के पास अद्वितीय विशेषज्ञता है। एएफपी समेत पत्रकारों को भेजे गए एक ऑडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि समझौतों के अनुसार, हमने जिन पहले तीन देशों को ये ड्रोन भेजे हैं, वे हैं कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। उन्होंने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर शाहेद हमलों को मार गिराने के मामले में, आज केवल यूक्रेनी अनुभव ही वास्तव में मददगार साबित हो सकता है।ष उनका इशारा रूस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानी डिजाइन के ड्रोनों की ओर था। उनके संचार सलाहकार ने पत्रकारों को यह भी बताया कि यूक्रेनी विशेषज्ञों को जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। जेलेंस्की ने खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों से यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर के बदले में बेहद जरूरी हवाई रक्षा मिसाइलें सौंपने का आह्वान किया है।

ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सैन्य ताकत तैनात करने की क्षमता। अमेरिका के पास दुनिया भर में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। 11 परमाणु संचालित विमान वाहक पोत हैं और हजारों विमान व टैंकर हैं। अब यूक्रेन की बात करें तो यह वो देश है जिसकी नौसेना को 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 में रूसी आक्रमण के दौरान लगभग नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस सूडान, माली और ईरान तक सक्रिय हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बुडानोव के शब्दों में हमारा मिशन है रूसी युद्ध अपराधियों को दुनिया में कहीं भी नष्ट करना। सूडान के गृह युद्ध में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक और जमीनी अभियान चलाए हैं। रूस के वागनर ग्रुप के भारी के सैनिकों के खिलाफ भी यूक्रेन ने मोर्चा खोला है। यह है यूक्रेन का ग्लोबल फुटप्रिंट और यह दिन–बदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहां यूक्रेन ने समुद्र में सबसे बड़ा धमाका किया है। 2022 में जब रूस ने हमला किया तब यूक्रेन के पास एक छोटी कमजोर नौसेना थी। रूस का ब्लैक सी फ्लट सैकड़ों युद्ध पोतों से लैस था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन इसे चुनौती दे सकता है। लेकिन यूक्रेन ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास की दिशा बदल दी। नेवल ड्रोंस समुद्री ड्रोन। मगरा ट5 यह एक 18 फुट लंबा कार्बन फाइबर का बना समुद्री ड्रोन है। इसकी कीमत महज 2.5 से 3 लाख है। लेकिन यह उन युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम है जिनकी कीमत अरबों डॉलर है। मई 2023 में तीन मगरा ट5 ड्रोनों ने रूस के 4000 टन के इवान खुर्स जासूसी जहाज पर हमला किया जो यूक्रेन से सैकड़ों मील दूर था। फरवरी 2024 में मगरा ट5 ने इतिहास रच दिया। यह दुनिया का पहला नेवल ड्रोन बना जिसने दुश्मन के युद्धपोधा को डुबोया। रूस का इवानोवेट्स गाइडेड मिसाइल कारवेबेट और सेजार कुनिकोफ लैंडिंग शिप दोनों को इसने तबाह किया। एक साल में मगरा ट5 ने आठ रूसी युद्धपोत नष्ट किए। छह को गंभीर नुकसान पहुंचाया। कुल नुकसान +50 करोड़ डॉलर से ज्यादा। 2025 के अंत तक कम से कम 20 रूसी युद्धपोत इसका शिकार बन चुके थे। एफपीवी का कामकाजे ड्रोंस ने जमीनी युद्ध की पूरी तस्वीर बदल दी। टैंक कॉलम्स जो कभी युद्ध में अजय माने जाते थे। अब यूक्रेनी एफपीवी ड्रोंस के सामने असहाय है। यूक्रेन ने एक साथ पांच रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। साइबेरिया जितनी दूर तक। नष्ट हुए रूस के स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बमबर्स, ट्रांसपोर्ट और एक इवक्स टाइप रिकनेसेंस एयरक्राफ्टरू यह हमला हुआ सस्ते क्वाडकोप्टर ड्रोंस से। इन ड्रोनों के पुरजे रूस में चुपके से स्मगल किए गए। वहां उन्हें असेंबल किया गया। युद्ध के मैदान में सस्ते लेकिन बड़े पैमाने पर किए गए ड्रोन हमलों की सफलता से अमेरिका भी चौंक गया। इसके बाद अमेरिका ने गुप्त रूप से शाहेद–136 ड्रोन को हासिल कर उनका तकनीकी विश्लेषण करने की कोशिश की। इन नमूनों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझा गया और उनके आधार पर प्रशिक्षण के लिए प्रतिरूप तैयार किए गए।

हड्डियां जलाने वाले गोले दागे, एक पायलट की तलाश में लेबनान के कब्रिस्तान क्यों खोद रहा इजरायल

अभिनय

कुछ ही दिन पहले ईस्टर्न लेबनान में देर रात एक ड्रामेटिक मिशन के दौरान इजराइल की स्पेशल फोर्सेस ने एक गांव में तलाशी शुरू की। किसी आम जगह या घर की नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान की। मिशन था 40 साल से लापता एक इजराइली पायलट की कब्र और उनके अवशेष खोजना। पर इजराइल का ऑपरेशन रातोंरात असफल हो गया। ऑपरेशन के दौरान इजराइयली कमांडोज और हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ–साथ कुछ लोगों के बीच गोलीबारी हो गई। इसके बाद इजराइली लड़ाकू विमानों ने इलाके पर हवाई हमले किए जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। लेबनीज आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस लड़ाई में तीन लेबनानी सैनिक और बेकावे वैली के 41 रेजिडेंट्स मारे गए हैं। वहीं इजराइली सैनिकों के घायल होने की कोई खबर अब तक नहीं मिली है। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका ईरान युद्ध जैसे–जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे–वैसे उसका अमानवीय पक्ष सामने आ रहा है। अब लेबनान के मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर कस्बे के रिहायशी इलाके पर सफेद फॉस्फोरस के गोले दागे, जिससे घरों और कारों में आग लग गई और लोग झुलस गए। संगठनों ने वीडियो और फोटो जारी कर दावा किया कि 3 मार्च के हमले में हवा में फटने वाले सफेद फॉस्फोरस के गोले इस्तेमाल किए गए, जिनसे जलते कण बड़े इलाके में फैल गए। ह्युमन राइट्स वॉच ने 7 तस्वीरों को सत्यापित किया है, जिनमें रिहायशी इलाके के ऊपर गोले फटते दिखाई देते हैं। संगठन ने कहा कि आबादी वाले इलाकों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ है। सफेद फॉस्फोरस बेहद ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत जल उठता है। जलने पर इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और हड्डी तक जला देता है। हवा में फटने पर यह 125 से 250 मीटर के दायरे में सैकड़ों जलते कण फैला देता है। इससे त्वचा और मांस गंभीर रूप से जल सकते हैं, जहरीला धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और घर, खेत व वाहन में आग लग सकती है। अमेरिका पर 2004 में इराक के फलूजा युद्ध में सफेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। इजराइल ने 2008 से 2009 गाजा युद्ध में इसके इस्तेमाल की बात मानी थी। 2023 में भी इजराइल पर गाजा और लेबनान में भी ऐसे हमलों के आरोप लग चुके हैं। 1980 में संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल–ण्ण के

तहत आग लगाने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर कड़े नियम बने। आबादी वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग प्रतिबंधिात है। सफेद फॉस्फोरस पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन नागरिक इलाकों में इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेबनीज आर्मी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10रू00 बजे दो इजराइली हेलीकॉप्टर सीरिया लेबनान सीमा पर बेकावे वैली में स्थित नबीचित और क्राइबे कस्बों के पास लैंड हुए। जिनसे इजराइली सैनिकों को नीचे उतारा गया। इसके बाद सैनिक नबीचित के कब्रिस्तान में पहुंचे और एक कब्र की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें यहां पर शक हुआ था कि वहां 1986 में लेबनान में लापता हुए इजराइली पायलट रॉन अराद के अवशेष दफन मिल सकते हैं। कई न्यूज प्लेटफॉर्म्स द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एक कब्र के पास ताजा खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। उस जगह थोड़ी देर के लिए खुदाई की गई थी और फिर इजरायली फोर्सेस वहां से वापस लौट गई। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इजराइयली हेलीकॉप्टर इलाके में उतरे तो लेबनी सेना ने इस घुसपैठ का पता लगा लिया और हेलीकॉप्टरों के ऊपर फ्लेयर डाली। इसके बाद इजराइयली सैनिकों, स्थानीय लोगों और हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। आईडीएफ यानी कि इजराइयली डिफेंस फोर्सेस ने इस दौरान शहर पर कम से कम 40 हवाई हमले किए। ऑन ग्राउंड इजराइली सैनिकों, स्थानीय लोगों और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई चलती रही जो सुबह करीब 3रू00 बजे तक जारी रही। द गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है घटना के वीडियो में लगातार गोलीबारी दिखाई दी जिसमें आसमान में ट्रेसर बुलेट साफ नजर आ रही थी। साल 1986 में इजराइल और लेबनान के उग्रवादी संगठन हजबुला के बीच लड़ाई हुई थी और इसके दौरान लेबनान के ऊपर से उड़ता हुआ एक इजराइली एयरक्राफ्ट एफ4 फैंटम टू फाइटर बम्बर मार गिराया गया था। इस एयरक्राफ्ट के नेविगेटर रॉन अराध थे और पायलट यशाई अविराम। अविराम सेफ रिजेक्ट हो गए थे। जिन्हें बाद में इजरयली फोर्सेस ने रेस्क्यू भी कर लिया था। पर इस घटना के बाद अराधा लापता हो गए। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद रॉन को शिया मिलिशिया अमाल मूवमेंट ने पकड़ लिया और बाद में हिजबुल्ला को सौंप दिया गया था। लेट 1980 के बाद से उनके जिंदा होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। 2004 में इजराइल के गवर्नमेंट कमीशन ने कंक्लूड भी किया था कि रॉन अराध की मौत मिड 1990 में हो चुकी थी। इसके बावजूद इजरयली सरकार उनके अवशेष ढूंढने की कोशिश करती रही है। 2021 में उस समय के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने कहा था कि इजराइली इंटेलिजेंस ने ईरान के एक जनरल को सीरिया से अगवा किया था ताकि अराद के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेबनान रीजन में यह आमतौर पर माना जाता है कि विमान दुर्घटना के कुछ समय बाद रॉन अराध की मौत हो गई थी और उन्हें बेका वैली के किसी इलाके में दफन कर दिया गया था। हालांकि उनकी कब्र की सही जगह कहां है? आज तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है।

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव 11 मार्च को लखनऊ में करेंगी बैठक

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव 11 मार्च को जनपद लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगी। इस दौरान वह महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक, महिला जनसुनवाई तथा विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण करेंगी।निध ारित कार्यक्रम के अनुसार उपाध्यक्ष प्रातः 10:30 बजे विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास से प्रस्थान कर 11:00 बजे राज्य महिला आयोग के सभागार, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमतीनगर पहुंचेंगी। यहां वह महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों और अन्य जनपदीय अधिकारियों के साथ महिला उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित बैठक में भाग लेंगी। बैठक के बाद उपाध्यक्ष महिला जनसुनवाई करेंगी, जिसमें पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधि त अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।इसके पश्चात उपाध्यक्ष 12:45 बजे राज्य महिला आयोग सभागार से प्रस्थान कर 1:00 बजे वन स्टॉप सेंटर, लखनऊ पहुंचेंगी। यहां वह केंद्र का निरीक्षण करेंगी और आयोजित महिलाओं की गोद भराई तथा अन्नप्राशन कार्यक्रम में भाग लेंगी।इसके बाद उपाध्यक्ष 1:30 बजे वन स्टॉप सेंटर से प्रस्थान कर 1:45 बजे लोक बंधु चिकित्सालय पहुंचेंगी। यहां वह चिकित्सालय का निरीक्षण करेंगी तथा आयोजित किट वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी।इन कार्यक्रमों के माध्यम से उपाध्यक्ष महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश भी प्रदान करेंगी।

शुक्रवार को किसानों के खाते में आएगी 22 वीं श्किसान सम्मान निधि’

(राजेश ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।शुक्रवार यानि कि 13 मार्च को किसानों के लिए अच्छा दिन साबित होगा।क्योंकि शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी असम से किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेजेंगे। इससे उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 4335.11 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक (21वीं किस्त) 94,668.58 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है।प्रतिवर्ष तीन किस्त में दी जाती है। इस तरह छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता किसानों को मिलती है।शुक्रवार को जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4335.11 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की ध नराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था।यूपी के किसानों के खाते में आ चुका हैं 94668.58 करोड़ रुपये' उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 21वीं किस्त तक 94668.58 करोड़ रुपये की धनराशि आ चुकी है। शुक्रवार को 4335.11 करोड़ जारी होने के बाद यह राशि 99003.69 करोड़ रुपये हो जाएगी।

आबकारी विभाग ने 1793 मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु ई–लॉटरी प्रक्रिया शुरू की

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप तथा भांग की दुकानों के ई–नवीनीकरण के बाद शेष बची कुल 1793 फुटकर दुकानों के आवंटन के लिए आबकारी विभाग ने ई–लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में आवेदन की प्रक्रिया आज से आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रारम्भ कर दी गई है।आबकारी विभाग द्वारा जारी नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश भर की मदिरा दुकानों का आवंटन ई–लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुगमता सुनिश्चित की जा सकेगी। इच्छुक आवेदक निर्धारित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।विभाग की ओर से बताया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन शुल्क, पात्रता की शर्तें तथा अन्य आवश्यक विवरण विभागीय वेबसाइट और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। इच्छुक आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि आवेदन करने से पहले सभी नियमों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें।आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया तकनीकी रूप से सुरक्षित और पारदर्शी बनाई गई है। ई–लॉटरी के माध यम से दुकानों का आवंटन निर्धारित समय–सारणी के अनुसार किया जाएगा।प्रदेश सरकार का उद्देश्य नई आबकारी व्यवस्था के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, राजस्व को सुदृढ़ करना और पूरी व्यवस्था को सरल तथा सुगम बनाना है।

नए शहरों के विकास के लिए आठ नगरों को 425 करोड़ रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव

लखनऊ, (संवाददाता)। नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के साथ ही बढ़ती शहरी आबादी को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरणध्नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के आठ नगरों के लिए धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना के अंतर्गत नए शहरों के समग्र और व्यवस्थित विकास के लिए शासनादेश दिनांक 6 अप्रैल 2023 के माध्यम से दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों के अनुसार भूमि अर्जन में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान है।वित्तीय वर्ष 2025–26 में नए शहरों के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के अंतर्गत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ में नए शहरों के समग्र विकास के लिए संबंधित अभिकरणों को सीड कैपिटल के रूप में कुल 425 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि जारी करने का प्रस्ताव है।सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से इन नगरों में योजनाबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे का विकास होगा और भविष्य की शहरी जरूरतों के अनुरूप आवासीय तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। इससे बढ़ती शहरी आबादी के लिए बेहतर आवासीय विकल्प उपलब्ध कराने के साथ ही संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए नजूल भूमि नगर निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव

लखनऊ, (संवाददाता)।जनपद अयोध्या में खेल सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए नजूल भूमि नगर निगम अयोध्या को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है।जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या के पत्र दिनांक 10 सितंबर 2025 के आधार पर यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

जौनपुर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत ,लंबित और प्री–लिटिगेशन मामलों का होगा निपटारा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,12 मार्च । यूपी के जौनपुर में जिला न्यायालय परिसर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च (शनिवार) को प्रस्तावित है। इस लोक अदालत में लंबित अदालती मुकदमों और प्री–लिटिगेशन (समझौता योग्य) मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, ई–चालान और बैंक वसूली से संबंधित मामलों का निस्तारण होगा। यह अदालत उन सभी मामलों को निपटाने का अवसर प्रदान करेगी जिनमें पक्षकार आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं। इस संबंध में गुरुवार को हिंदुस्थान समाचार प्रतिनिधि से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुशील कुमार सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाध ीश के निर्देश पर 14 मार्च को सुबह 10 बजे से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी सिविल वाद, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन और बीमा से संबंधित मामलों में लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत का सिद्धांत श्न किसी की हार, न किसी की जीतश् पर आधारित है, जिससे दोनों पक्षों को संतोषजनक समाध ान मिल सके। जिले के सभी पीड़ित लोगों से अपील की गई है कि वे 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर इसे सफल बनाएं।

आकाश पांडे और उमेश शर्मा की मौत पर परिजनों से मिले अजय राय

लखनऊ, (संवाददाता)। संतकबीर नगर निवासी आकाश पांडे और गोरखपुर निवासी उमेश शर्मा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को पीड़ित परिवारों से मिलने संतकबीर नगर और गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया।बताया गया कि निषाद पार्टी के एक नेता की फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर से दोनों युवकों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अजय राय मृतकों के आवास पहुंचे और परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर उनके साथ खड़ी रहेगी।अजय राय ने कहा कि निषाद पार्टी के नेता की गाड़ी से मेडिकल कॉलेज के छात्र आकाश पांडे और गोरखपुर निवासी उमेश शर्मा की मौत सत्ता के अहंकार को दर्शाती है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रदेश में रसूखदार नेताओं के बेटों और करीबियों को आम जनता की जान लेने की खुली छूट मिल गई है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य सरकार से मांग की कि दोनों पीड़ित परिवारों को एक–एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।अजय राय ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन प्रदेश में लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेगी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत अलीगंज में छात्राओं को किया गया जागरूक, पुलिस ने दी साइबर सुरक्षा और हेल्पलाइन की जानकारी

लखनऊ, (संवाददाता)। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत मंगलवार को थाना अलीगंज पुलिस टीम ने सुभाष चंद्र डिग्री कॉलेज,

पुरनिया अलीगंज में छात्राओं और शिक्षिकाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, साइबर अपराध से बचाव और यूपी कॉप एप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत लखनऊ कमिश्नरेट के 54 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है, ताकि थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।कार्यक्रम के दौरान उपनिरीक्षक रविन्द्र नाथ प्रजापति और उपनिरीक्षक प्रगति सिंह ने छात्राओं को 1090, 112 और 1930 जैसे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। साथ ही यूपी कॉप एप के माध्यम से पुलिस सहायता लेने की प्रक्रिया भी समझाई गई। छात्राओं को गुड टच और बैड टच जैसे संवेदनशील विषयों पर भी जागरूक किया गया तथा साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।पुलिस अध िकारियों ने छात्राओं को बताया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। उन्होंने साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से जुड़े खतरों के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा गोपनीयता के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्र–छात्राओं में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना है।

लखनऊ में बेटे ने लाठी से सिर पर वार कर की पिता की हत्या

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान बेटे द्वारा पिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में 17 वर्षीय बाल अपचारी ने अपने पिता के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बाल अपचारी को पकड़कर पुलिस संरक्षण में ले लिया है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। दक्षिणी जोन के पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंत कुमार के मार्गदर्शन और सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज विकास कुमार पांडेय की निगरानी में प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी बाल अपचारी को पकड़ने में सफलता हासिल की।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शोध से ऑयस्टर मशरूम उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीक विकसित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई और प्रभावी तकनीक विकसित की है। यह शोध अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्था Elsevier dh çfrf"Br if=dk Bioresource Technology Reports में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर चार से अधिक है। इस नई तकनीक में बरमूडा घास और प्रयुक्त मशरूम सब्सट्रेट (एसएमएस) के मिश्रण का उपयोग किया गया है। अध्ययन के अनुसार इस मिश्रण से न केवल मशरूम की पैदावार में वृद्धि होती है, बल्कि उसकी पोषण गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होता है। यह शोध बायोटेक्नोलॉजी विभाग के शोधकर्ता रोशन लाल गौतम ने विभागाध्यक्ष प्रो राम नारायण के निर्देशन में किया है। शोध के दौरान बरमूडा घास और एसएमएस को अलग–अलग अनुपात में मिलाकर मशरूम की खेती की गई। अध्ययन में पाया गया कि 80 प्रतिशत बरमूडा घास और 20 प्रतिशत एसएमएस का संयोजन सबसे अध िक प्रभावी रहा। इस संयोजन में मशरूम के माइसीलियम का विकास तेजी से हुआ और केवल 16 दिनों में पूरा माइसीलियल रन पूरा हो गया। इसी अनुपात में मशरूम की कुल उपज लगभग 1711 ग्राम दर्ज की गई, जबकि इसकी जैविक दक्षता 336.4 प्रतिशत रही, जो अन्य संयोजनों की तुलना में सबसे अधिक है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि एसएमएस के उपयोग से मशरूम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज तत्वों की मात्रा में भी वृद्धि होती है। शोध ाकर्ताओं के अनुसार यह तकनीक मशरूम उत्पादन को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल बना सकती है। प्रयुक्त मशरूम सब्सट्रेट के पुनः उपयोग से कृषि अपशिष्ट को उपयोगी जैव उत्पाद में बदला जा सकता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक किसानों और मशरूम उत्पादकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है और मशरूम आधारित कृषि को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

सांड की टक्कर से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार को मिला सहारा, शासन ने दी चार लाख की आर्थिक सहायता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर के बदलापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम छंगापुर निवासी स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद की सांड से टक्कर लगने के कारण हुई दर्दनाक मृत्यु के बाद शासन की ओर से उनके परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत मृतक की पत्नी श्रीमती मीरा नायक के खाते में भेजी गई है। 12 अगस्त 2024 को स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर आए एक छुट्टा सांड से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के बाद क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मामले की रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भेजी गई, जिसके आधार पर पीड़ित परिवार को शासन की योजना के अंतर्गत सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तक भी पहुंचा। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने मामले का परीक्षण कराया। जांच में पाया गया कि शासनादेश के अनुसार सांड एवं नीलगाय जैसे पशुओं के आघात से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा की श्रेणी में रखा गया है, जिसके अंतर्गत पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी बदलापुर और तहसीलदार के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों की जांच कर कार्यवाही पूरी की गई। 9 मार्च 2026 को मृतक के विधिक वारिस पत्नी श्रीमती मीरा नायक के खाते में चार लाख रुपये की सहायता राशि अंतरित कर दी गई। सहायता राशि मिलने पर श्रीमती मीरा नायक ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। जिला प्रशासन ने कहा कि पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता रहेगा।

ईंधन आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी की बैठक, घटतौली व मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में देर शाम जनपद के पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के 263 डीजल–पेट्रोल पंप संचालक, 92 गैस एजेंसी संचालक, विभिन्न ऑयल कंपनियों के जनपदीय बिक्री अधिकारी, सीएनजी अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि तथा खाद्य एवं रसद विभाग के अध िकारी और पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में डीजल, पेट्रोल अथवा घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी और अवैध भंडारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर जिले में ईंध न की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। जनपद में संचालित 263 पेट्रोल–डीजल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, जबकि 92 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति कराई जा रही है। बुकिंग के अनुसार निध ारित समय सीमा में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अपील की कि वे डीजल, पेट्रोल या गैस सिलेंडरों का अनावश्यक संग्रहण (होर्डिंग) न करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल शासन और जिला प्रशासन द्वारा जारी आधि ाकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले स्वामित्व दस्तावेजों की जांच अनिवार्य करने की तैयारी

लखनऊ, (संवाददाता)। संपत्ति के फर्जी या विवादित सौदों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रही है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, अब संपत्ति के पंजीकरण से पहले खतौनी और अन्य स्वामित्व से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन और परीक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।विभाग के अनुसार वर्तमान समय में कई मामलों में संपत्ति के वास्तविक स्वामी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा संपत्ति का विक्रय, प्रतिबंधित या निषिद्ध संपत्ति की बिक्री, किसी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार से अधिक संपत्ति का विक्रय, कुर्क संपत्ति का विक्रय या केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री कराए जाने जैसे मामले सामने आते रहते हैं। इससे जनसामान्य को मुकदमेबाजी और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा शासन और विभाग की छवि भी प्रभावित होती है।रजिस्ट्रीकरण अधि नियम और नियमावली के तहत किसी विलेख के पंजीकरण से इनकार करने के मामले में उप निबंधक को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की ध ारा 35 के अंतर्गत सीमित अधिकार प्राप्त हैं। इसी कारण कई बार विवादित या संदिग्ध संपत्तियों की भी रजिस्ट्री हो जाती है।इन समस्याओं के समाधान के लिए अन्य राज्यों में समय–समय पर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और नियमावली में संशोधन कर नियंत्रण स्थापित किया गया है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

यूपी में आधार बायोमीट्रिक अपडेट के लिए बड़ा अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड के बायोमीट्रिक अपडेट के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अब प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कैंप लगाकर विद्यार्थियों का आधार बायोमीट्रिक अपडेट कराएगा।अभियान के तहत ऐसे शिक्षण संस्थानों में कैंप लगाए जाएंगे जहां 500 या उससे अधि ाक छात्र अध्ययनरत हैं। इसके लिए प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। पहले यह व्यवस्था केवल उन स्कूलों में लागू थी जहां 1000 या उससे अधिक छात्र थे, लेकिन अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक सुविधा पहुंचाने के लिए अब यह सीमा घटाकर 500 कर दी गई है।यूआईडीएआई के अनुसार आधार में बायोमीट्रिक अपडेट 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनिवार्य होता है। इन दोनों आयु वर्गों में बच्चों की उंगलियों के निशान और आईरिस स्कैन दोबारा दर्ज किए जाते हैं, ताकि

गोसाईगंज में कई ट्रेनों का ठहराव के लिए सभासद ने डीआरएम को दिया पत्र

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।जिले के गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर सरयू–यमुना, कोटा–पटना एवं अमृतसर– जलियां वाला बाग एक्स0 ट्रेन का ठहराव दिए जाने को लेकर गुरुवार को गोसाईगंज नगर पंचायत की सभासद एवं जय बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति (रजि0) की अध्यक्ष आरती जायसवाल ने मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा को पत्र दिया। पत्र के माध्यम से जनहित में उपरोक्त सभी ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द सुनिश्चित कराये जाने की मांग की।पत्र के माध्यम से सभासद ने बताया है कि लखनऊ–बाराबंकी– जौनपुर– वाराणसी रेलखंड स्थित गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नं 13237ध्38,14649ध्50,18103ध्04 के ठहराव की मांग बहुत पुरानी है।जिसके सम्बन्ध मे बीते दिनों कई बार उनके द्वारा पत्र भी दिया गया,लेकिन इन गाड़ियों का ठहराव आज तक पूर्व सांसद एवं मौजूदा एमएलसी श्री हरिओम पांडे के होम स्टेशन में शुमार गोशाईगंज रेलवे स्टेशन सुनिश्चित नहीं हो सका।जिससे आज भी यात्रियों को इन ट्रेनों को पकड़ने के लिए अकबरपुर व अयोध्या कैंट स्टेशन तक भाग दौड़ करना पड़ता है। मालूम हो कि विधानसभा मुख्यालय स्थित गोसाईगंज स्टेशन अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा होने का साथ ही अयोध्या धाम जनपद के बॉर्डर पर स्थित है!मालूम हो कि इस सम्बन्ध मे पूर्व सांसद एवं मौजूदा एमएलसी हरी ओम पांडेय,पूर्व सांसद रितेश पांडेय,सांसद राम शिरोमणि वर्मा,विधायक अभय सिंह सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने कई बार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पत्र भेजा बावजूद इस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ और आज भी ये ट्रेने यात्रियों को मुंह चिढ़ाते गणतंव्य को चली जा रही है।

हमले मे दर्शननगर रेलवे कर्मी घायल

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) अयोध्या।अयोध्या कोतवाली के दर्शननगर रेलवे कालोनी निवासी एक रेल कर्मी पर हमले के मामले में पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कराई है।पुलिस को दी गई शिकायत में रेलवे कालोनी दर्शननगर निवासी दीपक कुमार रावत पुत्र अंबरीश कुमार का कहना है कि मंगलवार की शाम को वह दर्शननगर बाजार सब्जी लेने गया था।बाजार से सब्जी लेकर वापस आते समय सूर्यकुंड और जनरल स्टोर के पास के रहने वाले श्याम बाबू,राम बाबू,नानबाबू (लल्ला) तथा इनके दोस्तों पीछे से हमलाकर दिया। जातिसूचक गालियां दीं और जान से मार देने की धमकी दी। हमले में उनको गर्दन,सीने और सिर पर चोट आई।

अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो युवक घायल

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिले के अलग–अलग थाना क्षेत्र में अलग–अलग सड़क हादसों में महिला समेत दो घायल हो गए।दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बताते चले कि लखनऊ हाइवे पर पूरे काशीनाथ क्षेत्र में किसी वाहन की टक्कर से साइकिल सवार कैंट थाना क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी केशरी प्रसाद (70 वर्ष) पुत्र साहबदीन घायल हो गया।सूचना पाते ही घायल केशरी प्रसाद को एनएचएआई एंबुलेंस के ईएमटी अनुराग ने जिला अस्पताल पहुंचाया।वहीं नगर कोतवाली के सरयू विहार कालोनी के पास एक जेसीबी की टक्कर से वजीरगंज मोहल्ला निवासी निर्मला (60 वर्ष) पत्नी स्व. रामशंकर घ्याल हो गई,जिसको उसके बेटे नन्दीप ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

फरार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने किया 25–25 हजार का इनाम

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। एसएसपी ने जिला कारागार से फरार दोनों विचाराधीन बंदियों की गिरफ्तारी के लिए 25–25 हजार का इनाम घोषित किया है।प्रकरण में जिला कारागार के तत्कालीन जेलर ने दोनों के खिलाफ नगर कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।तब से पुलिस दोनों बंदियों की तलाश में लगी है, मगर एसओजी समेत तीन टीमों को लगाए जाने के बावजूद अभी इनका कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है।अब आम जन से इनका सुराग हासिल करने के लिए इनाम की घोषणा की गई है।28 जनवरी की रात जिला कारागार के विशेष सुरक्षा बैरक संख्या एक के कक्ष संख्या चार में निरुद्ध अमेठी जिले के मुसाफिरखाना निवासी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज और सुल्तानपुर के करौंदीकला थाना क्षेत्र स्थित अमेर मऊ निवासी शेर अली फरार हो गए थे।अगले दिन मामले की जानकारी पर हलचल मच गई थी।पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जिला कारागार का जायजा लिया था और जेल के कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था।मामले में नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और फरार बंदियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी। पुलिस कार्यालय का कहना है दोनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए इनाम की घोषणा की गई है।

'कस्टमर डे 2026– एयरटेल ने ग्राहकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपनी संस्कृति को और मजबूत किया'

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एयरटेल ने आज श्कस्टमर डे 2026श मनाया। यह संगठन के भीतर चलाया गया एक व्यापक अभियान है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की समस्याओं को समझना और उनके अनुभव को लगातार बेहतर बनाना है। इस पहल के तहत एयरटेल के लगभग बीस हजार कर्मचारियों ने अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर सीधे फील्ड में काम किया। इनमें नेतृत्व करने वाली टीम के सदस्यों से लेकर विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल थे। इन कर्मचारियों ने फ्रंटलाइन टीमों के साथ मिलकर काम किया, फील्ड इंजीनियरों के साथ जाकर उनके काम को करीब से देखा, घरों और दुकानों का दौरा किया और रिटेल व सर्विस सेंटरों पर ग्राहकों से बातचीत की। इसका उद्देश्य ग्राहकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को बिना किसी फिल्टर के समझना है। एयरटेल में कस्टमर डे संगठन के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर भी है जब वह ठहरकर आत्ममंथन करता है और खुद से एक सीधा लेकिन अहम सवाल पूछता है कि हम अपने ग्राहकों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए एयरटेल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शाश्वत शर्मा ने कहा, "कस्टमर डे हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हम ग्राहकों की बात पूरे ध्यान से सुनें, खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए चुनौती दें और तत्परता के साथ कार्रवाई करें। इससे ग्राहकों को होने वाली समस्याओं को हल करने, सेवाओं को सरल बनाने और हर दिन लाखों ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा के स्तर को लगातार बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।"

बहु को प्रताड़ित करने पर आरोपी सास को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने भेजा न्यायालय

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। बहु को प्रताड़ित करना तथा उसको मारना पीटना सास को महंगा पड़ गया। इस संबंध में महिला थाना अध्यक्ष आशा शुक्ला ने आरोपी सास को संबंधित धारा में न्यायालय भेज दिया।बताते चलें कि प्रताप रामपुर थाना हैदरगंज निवासी पीडिता बहू द्वारा महिला थाना आकर महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला को दिये गये शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि उसकी सास उसे आये दिन मारती पीटती है।इस दौरान पीडिता के चेहरे पर चोट के निशान भी दिखाई दे रही थी।इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया कि एक तरफ जहां पीडिता के चेहरे पर चोट के निशान थे।इस संबंध में जब उन्होंने आरोपी सास से पूछताछ किया तो यह प्रतीत हुआ कि वह आए दिन अपनी बहू को प्रताड़ित करते रहती है। जिसके चलते उन्होंने आरोपी सास को संबंधित धारा में न्यायालय भेज दिया।

एलवपीवजीव गैस समस्या को लेकर पूर्व मंत्री तेज नारायण पाडे पवन ने सौपां ज्ञापन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।गुरूवार को एलवपीवजीव गैस जनता तक सही समय पर न पहुंचने पर हो रही कठिनाइयों पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में महानगरध् अयोध्या विधानसभा ने कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौपा। इस मौके पर ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पूरे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत है जिसकी वजह से अयोध्या विधानसभाध् महानगर अयोध्या की जनता इस समय बहुत परेशान है।एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से जनता को सही समय पर बुकिंग के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है।जिसकी वजह से रसोई पर इसका गहरा असर देखा जा रहा है। इस मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि रमजान जैसा पवित्र महीना एवं शादिया व भंडारे का भी समय चल रहा है एवं दुख की घड़ी में लोगों के घरों में तेहरवी मे शांति भोज का कार्यक्रम भी रहता है बहुत से लोगों ने पहले से शादियों की तारीख तय कर ली है।आज उनके सामने गैस का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है।भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया मे बैठकर झूठ बोल रहे है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है।बल्कि सच ये है कि वो अपने खास लोगों को गैस दिला दे रहे और जनता को गुमराह कर रहे है उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, पूर्व मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने गैस समय से बुक कर दी है उनके घर तक बिना देरी किए हुए जिस तरह से पहले सिलेंडर पहुंचता था उसी तरह समय से होम डिलीवरी की जाए एवं जिनके घर वैवाहिक आयोजन प्रस्तावित है उनके लिए विशेष रूप से गैस सिलेंडर के इंतजाम कराया जाए एवं रमजान ऐसे पवित्र महीने में व उसके बाद ईद के त्यौहार में घरेलू गैस की अत्यधिक जरूरत पड़ती है ऐसे समय में उन लोगों को सही समय में गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जाए एवं एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए जिससे जनता अपनी समस्या संबंधित विभाग को अवगत करा सके जिससे जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े!!इस मौके पर महानगर महासचिव हामिद जाफर मीसम,उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव, अयोध्या विधानसभा अध्यक्ष रक्षा राम यादव, महिला महानगर अध्यक्ष अपर्णा जयसवाल, उपाध्यक्ष राकेश पांडे,प्रवीण राठौर, रियाज अहमद,अधिवक्ता सभा राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट शावेज जाफरी, महानगर अध्यक्ष अधिवक्ता सभा लाल बहादुर शुक्ल, मंसूर इलाही एडवोकेट, शादाब खान, जगदीश यादव, जगन्नाथ यादव, वीरेंद्र गौतम,अमृत राजपाल, शिक्षक सभा जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह, जेपी यादव,आरोनी पासवान,अजय यादव, शमशेर यादव, शहबाज लकी, राम आजोर यादव, ऋतुराज सिंह, प्रदेश सचिव पिछड़ा बृजेश सिंह चौहान, पूनम साहू, फहमीदा कुरैशी, रुक्मणी, ममता गुप्ता, एडवोकेट शशांक यादव, विजय नारायण यादव,नूर बाबू, रामचरण यादव, आशीष बर्मा, सुरेंद्र यादव, शिवपाल, महफूज उस्मानी, मुकेश,संजय यादव,नेहा यादव, अखिलेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक मे सीडीओ ने फैमिली आईडी में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने का दिया निर्देश

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे के निर्देश पर सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों एवं निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्ट्रीट लाइट योजना, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सड़क निर्माण, पेंशन योजना, फैमिली आईडी, ऑपरेशन कायाकल्प, पशु टीकाकरण, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, टेली रेडियोलॉजी तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि पेंशन से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित न रहे तथा फैमिली आईडी में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाई जाए।सीएमआईएस पोर्टल पर फीड परियोजनाओं की प्रगति के अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण, क्रीड़ा संकुल में छात्रावास निर्माण, सरयू नदी किनारे रैंप व जेटी निर्माण, धार्मिक पर्यटन स्थलों पर निर्माण कार्य, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, वृहद गौ संरक्षण केंद्र, सीसी रोड निर्माण कार्य, इंटरलॉकिंग, डिजिटल एलईडी, संपर्क मार्ग, जालपा नाले का विकास कार्य, सामुदायिक पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा मंडी स्थल पर पार्किंग निर्माण सहित संचालित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाए तथा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। जिन निर्माण परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें शीघ्र हैंडओवर कराया जाए, जिससे जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर अंकित सभी परियोजनाओं की प्रगति नियमित रूप से अपडेट की जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण किया जाए। जिन योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, उनमें तेजी लाते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्यस्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाए।

बैठक में पीडी, सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खंड विकास अधिकारी हुआ स्वागत

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। आईएएस परीक्षा उत करने वाले खंड विकास अधिकारी सोहावल अनुपम वर्मा को जिले के समस्त ब्लॉक पर तैनात खंड विकास अधिकारियो के द्वारा मसौधा ब्लॉक परिसर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया।इस मौके आयोजन करने वाले खंड विकास अधिकारियो ने कहा कि यह वास्तव में एक अत्यंत गर्व और अविस्मरणीय क्षण है कि अनुपम जी ने बी.डी.ओ. जैसे चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार पद पर कार्य करते हुए आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है।यह उनकी अद्भुत क्षमता, दृढ़ संकल्प और निरंतर परिश्रम का प्रतीक है।बी.डी.ओ. के साथ–साथ पीडीएस इकाई अयोध्या के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने हमेशा हम सभी की प्रतिष्ठा को सम्मान के साथ बनाए रखा।उन्होंने हर परिस्थिति में आगे बढ़कर नेतृत्व किया और अपने कार्यों से हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया।उचाधिकारियों के समक्ष इन्होंने अपनी बात हमेशा बेबाकी, निर्भीकता और स्पष्टता के साथ रखी, जो उनके मजबूत व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को दर्शाता है।ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वे जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें, नई ऊँचाइयों को प्राप्त करें और अपने कार्यों से समाज तथा देश का नाम और भी गौरवान्वित करें।इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अमित कुमार त्रिपाठी, अखिलेश मिश्रा, अनुराग सिंह, विकास मिश्रा, आनंद श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश मिश्रा, भावना यादव, हरिश्चंद सिंह व आरएस भारती मौजूद रहे

मऊशिवाला का एमआरएफ सेंटर प्रतिदिन करेगा 10 टन कूड़ा निस्तारण - महापौर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। कूड़ा निस्तारण कर नगर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक और बड़ा कदम उठाया है। स्वयंसेवी संस्था चिंतन की ओर से मऊशिवाला में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) का पुनर्विकास कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नई ऊंचाई प्रदान की गई है।चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप, नगर निगम अयोध्या के सहयोग से एसबीआई फाउंडेशन के सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत स्थापित इस इकाई का उद्घाटन महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने समारोहपूर्वक किया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त भारत भार्गव, सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडेय, एसबीआई फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक स्वप्न धर, रितेश सेन मुस्कान शर्मा, चिंतन संस्था की ओर से संस्थापक एवं निदेशक भारती चतुर्वेदी, अपूर्व अग्रवाल, मोहित गर्ग, आलोक सिंह राणा, एकता भटनागर, विमल कुमार, विनय कुमार उपस्थित रहे।महापौर ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि चिंतन एवं एसबीआई फाउंडेशन की इस पहल से ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन में आसानी होगी और नगर स्वच्छता रैंकिंग के उच्चतम शिखर की ओर बढ़ेगा।उन्होंने एसबीआईएफ के नारे श्वेस्ट नो मोर इन अयोध्याश को सार्थक बनाने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता जताई।उन्होंने कहा कि यह केंद्र आने वाले समय में अन्य शहरों के लिए प्रेरणादायक मॉडल के रूप में उभर सकता है। इससे अयोध्या को अधिक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में सफलता मिलेगी।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया मऊशिवाला में स्थापित एमआरएफ नगर निगम के चार वार्डों शिवनगर, चित्रगुप्तनगर, कृष्णानगर और लाला लाजपत राय नगर से एकत्रित कचरे का निस्तारण एवं प्रबंधन करेगा। इससे प्लास्टिक, कागज एवं अन्य पुनर्चक्रण योग्य संसाधनों की को रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त घरों से एकत्रित गीले कचरे का कम्पोस्टिंग के माध्यम से प्रसंस्करण कर जैविक खाद (कंपोस्ट) तैयार किया जाएगा,जिसका उपयोग पौधारोपण और नगर क्षेत्र में हरियाली लाने के लिए किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि केंद्र के माध्यम से प्रतिदिन 10 टन कूड़ा का निस्तारण किया जा सकेगा। चिंतन संस्था ने इसके लिए 14 कर्मचारियों की तैनाती की है। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से हर वर्ष साढ़े आठ लाख किलोग्राम कचरे को लैंडफिल में जाने से रोका जा सकेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

अफवाहों से न घबराएं,जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य – डीएम

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने जनपद में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रतिदिन लगभग 11 से 11.5 हजार घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग रहती है,जिसके अनुरूप लगातार आपूर्ति की जा रही है।डीएम ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कुछ बाधा आई थी,लेकिन उसे भी जल्द सुलझाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी पूरी तरह सामान्य है और सभी पेट्रोल पंपों पर सुचारू रूप से ईंधन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अफवाहों के कारण कुछ गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ और लंबी लाइनें लग गई थीं। इसको देखते हुए बुधवार को प्रशासन ने सभी गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक कर आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया।जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गैस एजेंसी पर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने न जाएं। गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को उनके क्रम के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा और होम डिलीवरी के माध्यम से घर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में गैस सिलेंडर बुकिंग का समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जिसके भीतर उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

विभागीय टीम ने कोटेदारों के कांटों की जांच व टेस्टिंग कराकर लगवाई नई सील

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। जिले के मिल्कीपुर तहसील स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में बुधवार को सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपयोग होने वाले कांटों (तराजू) की वार्षिक जांच की गई।इस मौके पर बाट एवं माप विभाग के अधिकारियों ने कांटों का परीक्षण कर उन पर नई सील लगाई।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण में सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोटेदारों के कांटों की हर वर्ष जांच की जाती है।इसी क्रम में बुधवार को विभागीय टीम ने कांटों का परीक्षण किया। टीम मे शामिल अधिकारियों ने जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया कि राशन वितरण में इस्तेमाल होने वाले कांटे पूरी तरह सही और निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। इन अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोटेदारों द्वारा राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा सही हो और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। यदि जांच में किसी कांटे में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे तत्काल ठीक कराया जाता है या बदलने के निर्देश दिए जाते हैं।जांच पूरी होने के बाद, सही पाए गए कांटों पर विभाग की ओर से नई सील लगाई गई। यह सील प्रमाणित करती है कि कांटे का परीक्षण हो चुका है और वह निर्धारित मानकों के अनुरूप है।विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की नियमित जांच से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है। इससे उपभोक्ताओं को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया कोटेदारों को भी नियमों के अनुरूप कार्य करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती है।अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी समय–समय पर इस प्रकार की जांच की जाती रहेगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और पात्र लाभार्थियों को उनका पूरा हक दिलाना है।

श्रीमद्भागवत कथा के जनजागरण के लिए निकली कलश शोभा यात्रा

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। मिल्कीपुर क्षेत्र के कहुआ गाँव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के जनजागरण के लिए बुधवार को विशाल भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई।कलश यात्रा को समीपवर्ती गांवों तथा देवस्थानों पर गाजे–बाजे के साथ निकालकर जन जागरण किया गया।कलश यात्रा की अगुवाई कथा प्रवाचक शिवम् शुक्ला महाराज, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री षटदर्शन संत समिति के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा, आवाहन अखाड़ा प्रयागराज के महामंडलेश्वर अरूण गिरि महाराज, स्वामी प्रकाशानंद महाराज गिरि ने किया। यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए सम्मिलित हुईं। कथा का आयोजन कहुआ गांव निवासी रोहित तिवारी ने किया है।हाथी, घोड़ा, और गाजे–बाजे के साथ के साथ निकली कलश यात्रा महादेवन मंदिर, हनुमान मंदिर कहुआ, शपनौतिन माता स्थान दसौली होते हुए कथा स्थल पहुंची। जहां पर आचार्यों ने विधि–विधान से पूजन के पश्चात कलश स्थापना संपन्न कराई। मंगल कलश सिर पर धारण किए हुए महिलाएं मंगलगीत गाते हुए चल रही थीं। जगह–जगह कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।यात्रा के दौरान देवी देवताओं के स्वरूप की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। कथा प्रवाचक ने व्यास पीठ के पूजन के साथ प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हुए श्रीमद्भागवत के महत्व पर प्रकाश डाला।कलश यात्रा में मुख्य यजमान रामावती तिवारी तथा भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, विधायक चन्द्रभानु पासवान, विनोद पांडेय, डॉ कपिल देव पांडेय, भवानी फेर मिश्र, शत्रुघ्न पांडेय, राकेश तिवारी, भानु प्रताप पाण्डेय, उमानाथ शुक्ल, डॉ देवेंद्र प्रताप शुक्ला, कृष्ण केवल मिश्र, अरूण गुप्ता, राज बहादुर शुक्ला राहुल, कुलदीप सिंह, जय हिन्द सिंह, अखिलेश दूबे, अखिलेश पांडेय, देवभान दूबे, संदीप तिवारी, सहित भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।